

भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी

प्रलिस के लयः

भारत की एकट ईस्ट नीतः, अंतरदेशीय जल परवहन, [भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग पराधकरण \(IWAI\)](#), लुक ईस्ट नीतः

मेन्स के लयः

भारत की एकट ईस्ट नीतः, भारत और पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध

[सरोतः पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पतन, पोत परवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मैया इनलैंड कस्टम पोर्ट से बांग्लादेश के सुलतानगंज पोर्ट के लयः पहले [प्रायोगिक मालवाहक जहाजों](#) (Trial Cargo Vessels) को हरी झंडी दरखाई जो [भारत की एकट ईस्ट नीतः](#) के तहत एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जसमें [अंतरदेशीय जल परवहन](#) को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रतः कयः गया है।

- इसका आयोजन [भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग पराधकरण \(IWAI\)](#) द्वारा कयः गया जो भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर कनेक्टवःतः तथा सहयोग की एक नई शुरुआत को दर्शाता है।

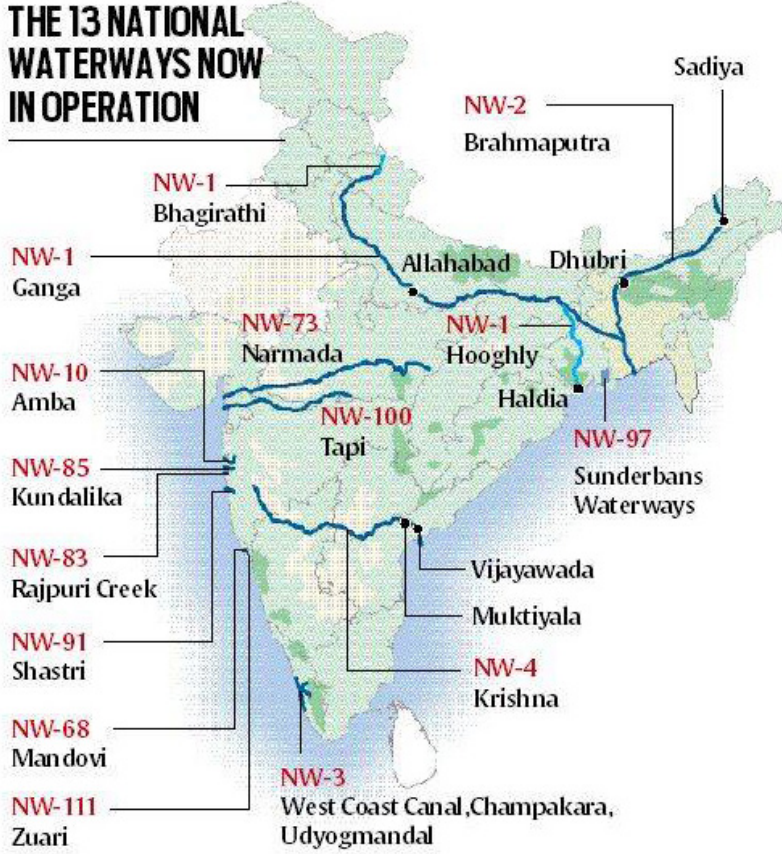
इस प्रायोगिक शपःमेंट का क्या महत्त्व है?

- माइया टर्मनःल के परचालन से बड़ा परवःर्तन होने की उम्मीद है क्योंकि यह बांग्लादेश जाने वाले 2.6 मलःयःन टन परतःवःर्ष (MTPA) नरःयात मालवाहक को सड़कमार्ग के स्थान पर जलमार्ग से परवहन करने की सुवधःा प्रदान करेगा।
- माइया-अरचा मार्ग (प्रोटोकॉल रूट 5 और 6) [NW1 \(राष्ट्रीय जलमार्ग 1\)](#) से बांग्लादेश और उत्तर पूरवी क्षेत्र की दूरी 930 कःलःमीटर कम कर देगा।

अंतरदेशीय जल परवहन (IWT) क्या है?

- परचयः**
 - IWT नौगम्य नदःयः, नहरों, झीलों और अन्य अंतरदेशीय जलमार्गों के माध्यम से माल तथा यात्रःयःों के परवहन को संदःर्भतः करता है।
 - इस प्रकार के परवहन में देश के आंतरकः क्षेत्रों में माल और लोगों के यातायात, जल मार्गों के साथ वभिन्ःन पतःतनों तथा टर्मनःलों को जोड़ने के लयः नावों, बजरों (Barge) एवं जहाजों जैसे माध्यमों का उपयोग कयः जाता है।
- महत्त्वः**
 - IWT परवहन का, वशःष रूप से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उरवरक जैसे बड़ी मात्र के माल परवहन के लयः एक **अत्यधःकः लागत प्रभावी तरःका** है।
 - इसके लाभों के बावजूद **भारत के मॉडल मशःरण** में इसकी वर्तमान **हसःसेदारी केवल 2% है। मैरीटाइम इंडया वःज़ःन (MIV)-2030** के तहत सरकार का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक इस हसःसेदारी को 5% तक बढ़ाना** है।
 - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लयः IWAI ने व्यवहार्यता अधःयन के माध्यम से 25 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (NW) की पहचान की है ताकः उन्हें परवहन के लयः नौगम्य बनाया जा सके।

THE 13 NATIONAL WATERWAYS NOW IN OPERATION



THE LINKS AND THE LENGTHS

NW-1	Ganga–Bhagirathi–Hooghly (Haldia–Allahabad)	1,620 km
NW-2	Brahmaputra river	891 km
NW-3	West Coast Canal–Champakara Canal–Udyogmandal Canal	205 km
NW-4	Krishna (Muktiyala–Vijayawada)	82 km
NW-10	Amba river	45 km
NW-83	Rajpuri Creek	31 km
NW-85	Revadanda Creek–Kundalika river	31 km
NW-91	Shastri river–Jaigad Creek System	52 km
NW-68	Mandovi river (Usgaon Bridge–Arabian Sea)	41 km
NW-111	Zuari river (Sanvordem Bridge–Marmugao Port)	50 km
NW-73	Narmada river	226 km
NW-100	Tapi river	436 km
NW-97	Sunderbans Waterways	172 km

एकट ईसट पॉलिसी क्या है?

परिचय:

- नवंबर, 2014 में घोषित **'एकट ईसट पॉलिसी'** **'लुक ईसट पॉलिसी'** का अपग्रेड है।
- यह वभिन्न स्तरों पर वशिल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है।
- इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन एवं नरिंतर जुड़ाव शामिल है।

उद्देश्य:

- इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और सक्रिय तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ **भारत-प्रशांत क्षेत्र** के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना एवं इस तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र (North Eastern Region- NER) के आर्थिक विकास में सुधार करना, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रवेश द्वार है।



India Acts East

With its Act East policy, India hopes to deepen its political, economic and security relationships with the countries of Southeast Asia and the wider Indo-Pacific. Balancing against the rise of China is a key driver.

China: India views the rise of its principal strategic rival as a serious challenge and is forging relations with countries along its periphery to maintain the balance between them

ASEAN: Boosting exports with the 10 members of the Association of Southeast Asian Nations is a core plank of Modi's Act East policy Australia: China's rise has compelled India's outreach to Australia to forge a stronger defense partnership

Australia: China's rise has compelled Indian outreach to forge a stronger defense partnership

Japan: The key regional power shares India's concerns over China's expansion

Northeast India: New Delhi wishes for its remote northeastern wing to serve as a trading hub that connects to Southeast Asia through Myanmar

South Korea: India wants to deepen trade, investment and security ties with this regional economic power

लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है?

- **सोवियत संघ (USSR)** के वधितन (शीत युद्ध वर्ष 1991 की समाप्ती) के साथ एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार को खो देने की भरपाई के लिये भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में उसके सहयोगी देशों के साथ संबंध नरिमाण की दशिया में आगे बढ़ा ।
- इस क्रम में भारत के **पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसमिहा राव ने वर्ष 1992 में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता को एक रणनीतिक बल देने के लिये 'लुक ईस्ट' नीतिका शुभारंभ कया** ताकि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में तथा चीन के रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के लिये अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके ।

लुक ईस्ट पॉलिसी और एकट ईस्ट पॉलिसी के बीच क्या अंतर है?

■ लुक ईस्ट पॉलिसी:

- लुक ईस्ट पॉलिसी में **'दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ' (आसयान)** तथा उनके आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कया गया ।
 - **भारत वर्ष 1996 में आसयान का एक संवाद भागीदार** और वर्ष 2002 में शखिर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना ।
 - वर्ष 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल गया ।
 - वर्ष 1992 में जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, उस समय आसयान के साथ भारत का व्यापार 2 बलियन अमेरिकी डॉलर था । वर्ष 2010 में आसयान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापार बढ़कर 72 बलियन अमेरिकी डॉलर (2017-18) हो गया है ।
 - भारत 'पूर्वी एशिया शखिर सम्मेलन' (EAS), 'आसयान क्षेत्रीय मंच' (ARF) आदि जैसे कई क्षेत्रीय मंचों में भी सक्रिय भागीदार है ।

■ एकट ईस्ट:

- एकट ईस्ट पॉलिसी **आसयान देशों + आर्थिक एकीकरण + पूर्वी एशियाई देशों + सुरक्षा सहयोग** पर केंद्रित है ।
 - भारत के प्रधानमंत्री ने **एकट ईस्ट पॉलिसी के '4C'** का उल्लेख कया है ।
 - संस्कृति (Culture)
 - वाणज्य (Commerce)
 - संपर्क (Connectivity)
 - क्षमता नरिमाण (Capacity building)
 - सुरक्षा भारत की एकट ईस्ट नीतिका एक महत्त्वपूर्ण आयाम है ।
 - **दक्षिण चीन सागर** और हदि महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में, नेवगिशन की स्वतंत्रता तथा हदि महासागर में भारत की अपनी भूमिका सुनिश्चित करना एकट ईस्ट पॉलिसी की एक प्रमुख विशेषता है ।
 - इसके अनुसरण में, भारत **क्वाड** नामक इंडो-पैसिफिक और अनौपचारिक समूह के आख्यान में शामिल हो गया है ।

एकट ईस्ट पॉलिसी के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने की क्या पहलें हैं?

- भारत और बांग्लादेश के बीच **अगरतला-अखौरा रेल संपर्क** ।
- **बांग्लादेश के माध्यम से इंटरमॉडल परविहन** संपर्क और अंतरदेशीय जलमार्ग ।
- **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट** और उत्तर पूर्व को म्यांमार तथा थाईलैंड से जोड़ने वाली **त्रपिकीय राजमार्ग परियोजना** ।
- **भारत-जापान एकट ईस्ट फोरम** के तहत, सड़क और पुल तथा जल-वदियुत ऊर्जा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं ।
 - इंडिया-जापान एकट ईस्ट फोरम की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की "एकट ईस्ट पॉलिसी" और जापान की "मुक्त एवं खुली भारत-प्रशांत रणनीति" के तहत भारत-जापान सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करना है ।
 - फोरम भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिये वशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करेगा, जिसमें कनेक्टिविटी, वकिसात्मक बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक संबंधों के साथ-साथ पर्यटन एवं संस्कृति तथा खेल-संबंधी गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्कता शामिल है ।
- **अन्य पहल:**
 - महामारी के दौरान **आसयान देशों को दवाओं के साथ-साथ चकितिसा आपूर्ति** के रूप में सहायता प्रदान की गई ।
 - आसयान देशों के प्रतभागियों के लिये **IIT में 1000 PhD फेलोशिप** की पेशकश के साथ छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ।
 - भारत शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र के **मूलभूत समुदायों को वकिसा सहायता प्रदान करने के लिये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वयितनाम** में त्वरति प्रभाव से परियोजनाएँ भी लागू कर रहा है ।
 - त्वरति प्रभाव परियोजनाएँ (QIP) छोटे पैमाने की, कम लागत वाली परियोजनाएँ हैं जिनकी योजना बनाई जाती है और उन्हें कम समय सीमा के भीतर कार्यान्वित कया जाता है ।
 - तटीय नौवहन एवं अंतरदेशीय जल परविहन के मॉडल शेर को बढ़ाने के लिये **अमृत काल वजिन 2047** में 46 पहलों की पहचान की गई है ।
 - प्रमुख पहलों में बंदरगाह-आधारित समूह केंद्रों का नरिमाण, उत्पादन एवं मांग केंद्रों के पास तटीय घाट और सड़क, रेल तथा अंतरदेशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी में सुधार के लिये परियोजनाएँ शामिल हैं ।
 - इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 50 जलमार्गों को चालू करना और साथ ही दक्षता तथा पहुँच बढ़ाने के लिये संभावित टग-बारज संयोजनों के साथ कम-ड्राफ्ट पोत डिज़ाइन प्रस्तुत करना है ।

??????:

प्रश्न.1 'रीजनल काम्प्रहिनसवि इकोनॉमिकि पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership)' पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? (2016)

- (a) जी- 20
- (b) आसियान
- (c) एस.सी.ओ.
- (d) सारक

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 10 राष्ट्र जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) बनाते हैं और साथ ही पाँच राष्ट्र जनिके साथ आसियान के वर्तमान में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के पक्षकार हैं।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

प्रश्न.2 मेकांग-गंगा सहयोग जो कछिह देशों की एक पहल है, नमिनलखिति में से कौन-सा/से देश प्रतभागी नहीं है/हैं? (2015)

1. बांग्लादेश
2. कंबोडिया
3. चीन
4. म्याँमार
5. थाईलैंड

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1, 2 और 5

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहति म्याँमार, बांग्लादेश और पाकस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का वशिलेषण कीजिये। वभिन्निन सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में नभियाई गई भूमिका की वविचना भी कीजिये। (2020)

प्रश्न. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्याँमार से लगी लंबी छदिरलि सीमाओं की दृष्टिसे भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं? (2013)